

18 88

He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—सम्ब 3—उप-सम्ब (II) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 205] No. 205] नई विल्लो, मंगलवार, अप्रैल 23, 1985/वैज्ञाख 3, 1907 NEW DELHI, TUESDAY, 23rd APRIL 1985/VAISAKHA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संदया की काली है जिससे कि यह अक्तग संकलन को अन्य में रका का सक

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाए

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

का. आ. 350(अ).....केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष स्थायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त मन्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के गृह मज्ञालयकी अधिसूचना मं० सा०का० नि० 290(अ) दिनांक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक ओन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष स्थायालय की स्थापना की है;

और गंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी हैं, जिसमें इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत उक्स अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का उक्त अधिनियम की घारा 4 की उप-धारा (2) के उपबंधों का इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में, विनिर्विष्ट मामले के तच्यों और प्ररिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत वालों का घ्यान रखने हुए यह राय है कि यह समोवोन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष स्थायालय द्वारा विवारण किया जाना वाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवस्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए यह चौथित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

	अनु त् ष'		
मामले की विशिष्टियां —	निम्नलिखित अधि	नियम के अधीन अपराध	स्यायिक जोत, जिसमें भवराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)	, , ,
1	2	3	Ą
प्र मु.रि. सं. 52 दिनोक 7-3-1984 घारा (पुलिस थाना सबर नामा)	302 और 307	भ्रारा 25 (।),स्रथ्ड (स्र)को छोड़कर औरभ्रारा 27	पटियाला
<u> </u>			f

[फा. सं. 5/1/85 विधिक एकक]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd April, 1985

S.O. 350(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated, the 22nd March, 1985.

And whereas the Se.te Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offences under the		Judicial Zone in which sa	
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act, 1959 (54 of 1959)	onences were con	committed
(1)	(2)	(3)		(4)
FIR M). 52 dated 7th March, 1984 (Police Station, Sadar Nabha)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala.	

[F. No. 5/1/85-Legal Cell]

का. आं. 351(अ),—केन्द्रीय सरकार ने आसंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की ⊨घारा 4 की उप धारा (2) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिमूचना सा. का. नि. सं. 289(अ) दिनोक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में जालन्घर के न्यायिक जोन की बावत राजस्थान राज्य में जोयपुर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट मेजी है जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिश्ट अपराक्षों की बावत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की घारा 4 को उनआरा (2) के उनबंदों का, इसते उनाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी मुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए यह राग है कि यह ममीबीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में औद्यपुर में स्थापित अतिरिक्त विशेष स्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए।

अतः अतः क्रेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियमकी धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रवस्त कवितयों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उन्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में जोधपुर में स्थापित अतिरिक्त विगेष स्थायालय द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		स्यायिक औन जिसमें अपराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)	
1	2	3	4
ा.सु.रि.सं. 44 दिनोक 1-3-1984 (पुलिस थाना नगर तरमसारन अमृतसर)	घारा 342 भीर 392	घारा 25(1), खण्ड (ख)को छो।	≇कर जालश्वर

[फाईल सं. 5/2/85-सीगल सैल]

S.O. 351(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Jodhpur in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Jalandhar in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 289(E) dated the 22nd March, 1985.

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 or the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offence	Offences under the Judicial Zone	
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	- offences were committed
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 44 dated 1st March, 1984 (Police Station-City Taran Taran, Amritsar)	Sections 342 and 392	Section 25 (1) excluding clause (b)	J. landhar

[F. No. 5/2/85-Legal Cell]

का. आ. 352 (आ).—केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61)(जिसे इसके बाद उपत अधि-नियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उप-धारा 2 द्वारा प्रवत्त मिन्तयों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के गृह मंद्रालय कर अधिसूचना सं. सा. का. नि. 290 (अ), दिनोक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी है, जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत् उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है;

े और केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार को, उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबंधों का, इससे उपायद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी मुसंगत बातों का ध्यान रखने हुए यह राज है कि यह समीकोत है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विवारण किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उस्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवत्त ग्रानिक्यों का प्रयोग करने हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अन्सूची

मामले की विशिष्टियाँ	निम्नलिखित अधि	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		
	भारनीय वण्ड संहिना 1860(186	0 का 45) आस्थ्र अधिनियम 1959(1959 व 54)	∵– किंमे गए का	
1	2	3	4	
प्र.सू.रि.सं. 69, विनोक 27-3-198 (पुलिस यामा-धनौला, जिला संगर		धारा 25(1),खण्ड (ख) को छो . कर और घारा 27	् - पटियाला	

[फा. सं० 5 / 3 / 8 5- विधिक एक क]

S.O. 352(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984(61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March, 1985.

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offences under t	Offences under the		
	Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	Offences were committed	
(1)	(2)	(3)	(4)	
FIR No. 69 dated 27th March, 1984 (Police Station-Dh. n. ula Distt (Sangrur)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala	

[F.No. 5/3/85-Legal Cell]

का. था. 353 (प्र):— केन्द्रीय सरकार ने धार्तकवार्थ केल (विशेष न्यायालय) श्रवितियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त प्रवितियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रवर्तत गक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मैदालय की प्रविस्तान संबंधा 290(प्र), दिनांक 22 मार्च, 1985 के प्रधान, पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में धाजमेर में एक प्रतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किया है;

ग्रीर पंजाब राज्य की सरकार ने केन्द्रोय सरकार की एक रिपोर्ट भैजी है, जिसमें इससे उपाबद प्रमुखी में बिनिर्दिष्ट प्रपराधों की बाबत उक्त ग्रधि-नियम की ग्रारा 7 की उप-धारा (2) के मर्धन घोषणा करने के लिये भनुरोध किया गया है;

भीर केन्द्रं य सरकार की राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त प्रधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपवेधों का, इससे उपायद्ध प्रनुपूषी के स्तम्भ 1 में विनिविष्ट मामले के तथ्यों भीर परिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत वातों का ध्यान रखते हुए यह राम है कि यह सभ की है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विगेष न्यायालय द्वारा विजारण किया जाना चाहिये;

भ्रतः, भ्रव केर्न्द्रय सरकार उक्त मिश्वनियम की धारा 7 को उपधारा (2) हारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त भ्रमराधों का विचारण राजस्थान राज्य में भ्रजमेर में स्थापित श्रतिरिक्त विशेष न्यायालय हारा किया जाएगा।

प्रनुस्ची

मामले की विणिष्टियां	निम्नलिखित भीधिनियम के भंतर्गत भपराध		न्यायिक जोन जिसमें प्रपराध किए गए
	भारत य वंड संहिता 1860 (1860 का 45)	भागुब भिधिनियम,	ALSIG THE SEC
(1)	(2)	(3)	(4)
प्र. सु. रिपोर्ट संख्या 180 विनांक 23 मई, 1984 (पुलिस थाना- सदर पटियाला)	घारा 302 मीर 307	धारा 25(1) खंड (ख को छोड़कर भीरधारा 27) पटियाला

[फा. सं. 5/4/85-विधिक एकक]

S.O. 353(E).—Whereas the Central G. vernment, in exercise of the powers conferred by sub-section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March 1985;

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed bareto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court est blished at Ajmer in the State of Rajasth. n;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

107 G.I./85--2

SCHEDULE

Particulars of the Case	Offences under the		Judicial Zone in which the
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act, 1959 (54 of 1959)	onences were commuted
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 180 dated 23rd May, 1984 (Potice Station-Sadar Patiala)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala

[F.No. 5/4/85-Legal Cell]

का. भा. 354(भ्र.) :—केन्द्रीय सरकार ने भ्रांतकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) प्रधिनियम, 1984 (1984 का 61) जिसे इसके बाद उक्त म्रिक्सिम कहा जायेगा) की सारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंग्रालय की प्रधिसूचना सा. का. नि. सं. 290 (भ्र) दिनांक 22-3-1985 के प्रधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में ग्रजमेर में एक मितिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है;

श्रीर पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजों है जिसमें इसमे उपाबद्ध मनुसूची में विनिर्दिष्ट मपराधों की बावत उक्त मिधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के श्रधीन भोषणा करने के लिये अनुरोध किया गया है;

भीर केन्द्रीय सरकार को, राज्य भरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों का, इसमे उपायदा अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिधिष्ट मामले के तथ्यों भीर परिस्थितियों का, तथा धन्य मर्मा सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, यह राय है कि यह ममीजीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अज़मेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिये।

भतः, भव, केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 7 की उपवारा (2) द्वारा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में भजमेर में स्थापित स्रतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित प्रधिनियम के प्रंतर्गत प्रपराघ		स्यायिक जोन जिसमें उक्त भ्रपराश्च किए गए
	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)	मायुष मधिनियम 1959 (1959 का 54)	जना जाराज सम्बन्ध
(1)	(2)	(3)	(4)
प्र. स्. रि. सं. 47 दिनांक 24-4-1984 (पुलिस थाना- ग्रमरगढ़, जिला संगरूर)	धारा 302/34	धारा 25(1) खंड (ख) को छोड़कर	पदियाला
		िका॰ स. 5/	

S.O. 354 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March 1985;

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of sction 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of the Rajasthan.

	SCHEDU	JLE	
Particulars of the Case	Offences under the		Judicial Zone in which said
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	onenees were committed
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 47 dated 24th April, 1984 (Police Station-Amarg rh, District, Sangrur)	Sections 302/34	Section 25(1) excluding clause (b)	Patiala
			[f. No 5/5/85 Legal Cell] L.N. GUPTA, Addl. Secy.